खंड १४ नंबर २ अप्रैल २०१८

आरआईएस डायरी

–अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

बुनियादी ढांचा भारत की प्राथमिकताओं के केंद्र में है

–श्री अरुण जेटली

वर्ष 2018 में भारत 22 से 27 जून तक मुंबई में एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की तीसरी वार्षिक बैठक की मेज़बानी करने जा रहा है। भारत के साथ–साथ एआईआईबी के अन्य सदस्य देशों में भी बुनियादी ढांचे के विभिन्न क्षेत्रों में निहित अनगिनत अवसरों एवं चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एआईआईबी की वार्षिक बैठक से पहले बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण से जुड़े प्रासंगिक मुद्दों पर कई संबंधित कार्यक्रमों की संकल्पना करने, योजना बनाने और आयोजित करने के लिए आरआईएस को 'ज्ञान भागीदार' बनाया है। इस श्रृंखला के एक हिस्से के रूप में आरआईएस विभिन्न उद्योग संगठनों जैसे कि भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की), एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया (एसोचैम) और भारतीय आयात–निर्यात बैंक (एगसिम बैंक) के सहयोग से इस वार्षिक बैठक से पहले आवश्यक समझे जाने वाले अनेक संबंधित कार्यक्रम आयोजित करेगा। नई दिल्ली में 27 फरवरी 2018 को पूर्वावलोकन समारोह के अलावा मार्च से जून 2018 तक भारत के विभिन्न शहरों में बुनियादी ढांचे से जुड़े विभिन्न विषयों (थीम) पर 8 संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जून 2018 में वार्षिक बैठक के दौरान कई 'मेजबान देश सेमिनारों' का आयोजन पृथक कार्यक्रमों के रूप में होगा। बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण से जुड़े कार्यक्रम इन विषयों पर होंगे: वित्तपोषण के स्रोत एवं साधन; कानूनी, संस्थागत एवं गवर्नेंस मुद्दे; अत्याधुनिक, सुदृढ़ एवं डिजिटल बुनियादी सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे में निवेश के उभरते क्षेत्र, महिला–पुरुष से जुड़ा बुनियादी ढांचा; नई प्रौद्योगिकी विकल्प; विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रवाह को बाधित

माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली नई दिल्ली में आयोजित एआईआईबी की वार्षिक बैठक के पूर्वावलोकन समारोह में उद्घाटन भाषण देते हुए।

माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और नौवहन मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी और आवास एवं शहरी मामलों के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी 'नए वित्त पोषण' पर आयोजित सत्र के दौरान प्रमुख व्यक्ताओं के साथ।

> ''भारत न केवल पारंपरिक आधारभूत संरचना, बल्कि ग्रामीण ढांचागत सुविधाओं के संदर्भ में भी बुनियादी ढांचे के निर्माण की आंकाक्षा रखता है।''
>
> "एशिया वह क्षेत्र है जिसे परंपरागत रूप से बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ा। और एशिया वह क्षेत्र है जहां पिछले कुछ दशकों में विकास ने तेज गति पकड़नी शुरू की है.... इस तरह से वह बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में पहले से मौजूद कमी को पूरा कर रहा है। यही वह क्षेत्र है जो विकास के मामले में पूरी दुनिया की अगुवाई करता रहा है।"
>
> – श्री अरुण जेटली

शेष पृष्ठ 12 पर जारी.....

प्रबुद्ध मंडलों के आसियान–भारत नेटवर्क (एआईएनटीटी) का पाँचवां सम्मेलन

आरआईएस स्थित आसियान–इंडिया सेंटर (एआईसी) ने इंडोनेशियाई विज्ञान संस्थान (एलआईपीआई), जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय मिशन, आसियान सचिवालय, भारत के विदेश मंत्रालय और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय के सहयोग से जकार्ता, इंडोनेशिया में 6–7 जनवरी 2018 को प्रबुद्ध मंडलों (थिंक टैंक) के आसियान–भारत नेटवर्क (एआईएनटीटी) के पाँचवें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इस गोलमेज सम्मेलन का शीर्षक था 'आसियान और भारतः एशिया में एकीकरण के साझेदार'। आसियान देशों और भारत के कई विशेषज्ञों एवं विद्वानों ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रों में पहले से स्थापित संबंधों को और मजबूत करने के लिए आपस में विचारों का आदान–प्रदान करने हेतु इस सम्मेलन में भाग लिया।

श्री सुरेश रेड्डी, आसियान में भारत के राजदूत, ने स्वागत भाषण दिया। भारत की माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने उद्घाटन भाषण दिया। इंडोनेशिया की माननीया विदेश मंत्री श्रीमती रेटनो मार्सुडी ने मुख्य भाषण दिया। आसियान के महासचिव माननीय श्री लिम जॉक होई ने धन्यवाद भाषण दिया। धन्यवाद ज्ञापन प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, नई दिल्ली द्वारा पेश किया गया। 'आसियान–भारत : आपस में बांधने वाले संबंधों को सुदृढ़ बनाने' पर चौथी एआईएनटीटी कार्यवाही इस सम्मेलन में जारी की गई। सभी

भारत की माननीया विदेश मंत्री और इंडोनेशिया की माननीया विदेश मंत्री 'एआईएनटीटी रिपोर्ट' जारी की।

आसियान देशों ने गोलमेज सम्मेलन के लिए अपने अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को नामित किया वरिष्ठ अधिकारियों सहित 100 से भी अधिक प्रतिभागियों ने इस पाँचवें एआईएनटीटी सम्मेलन में भाग लिया।

इस सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए पांच प्रमुख सत्र आयोजित किए गए थेः आसियान और भारत के बीच उन समुद्री चुनौतियों की पहचान करना जिनका समाधान अधिक सहयोग के जरिए करने की आवश्यकता है; आसियान एवं भारत के बीच सेवा व्यापार के अवरोधों की समीक्षा करना, ताकि आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सिफारिशों की एक श्रृंखला पेश की जा सके; आसियान एवं भारत की सांस्कृतिक विरासत की चर्चा करना और साझा सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के दायरे एवं अवसरों की पहचान करना; शैक्षणिक सहयोग की बाधाओं की पहचान करना एवं साझेदारी को मजबूत करने के लिए आगे की राह तैयार करना; और आसियान आर्थिक समुदाय (एईसी) की संभावनाओं एवं चुनौतियों और भारत एवं अन्य संवाद साझेदारों के लिए निहितार्थ पर चर्चा करना। परिचर्चा में विभिन्न घटकों का विश्लेषण करने के साथ–साथ उन्हें एकजुट करने का प्रयास किया गया जिससे आसियान और भारत के बीच साझेदारी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम का समापन डॉ. प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी सम्मेलन सार प्रस्तुती किया और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

भारत–ब्राजील–दक्षिण अफ्रीका पर संवाद

हाल के महीनों में आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के लिए घरेलू और बाह्य क्षेत्रों को एकीकृत करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों, विकास अध्ययनों और नीति निर्धारण के साथ परस्पर प्रभाव पर सूचित बहस का विश्लेषण करने की जरूरत को रेखांकित किया गया है। आरआईएस एक साझा प्लेटफॉर्म स्थापित करने की इस प्रक्रिया में है जहां सभी हितधारक नीतिगत सामंजस्य के विकास के लिए अपने विचारों का आदान–प्रदान कर सकते हैं। इस लक्ष्य की तरफ पहल करते हुए आरआईएस ने 13 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में 'विकास अध्ययनों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सार्वजनिक नीति के लिए शोधकर्ताओं के बीच बातचीत' पर विशेष सत्र आयोजित किया। डॉ. मोहन कुमार, उपाध्यक्ष, आरआईएस और श्री एस. टी. देवारे, अध्यक्ष, आरआईएस अनुसंधान सलाहकार परिषद ने इस परिचर्चाओं की अगुवाई की।

शहरी क्षेत्रों के लिए त्वरित जन परिवहन प्रणालियां : अवसर और चुनौतियां

उद्घाटन सत्र में उपस्थित कई प्रतिष्ठित प्रतिभागी।

जैसा कि बताया गया है, भारत सरकार जून 2018 में मुंबई में एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की तीसरी वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगी। इस संबंध में आरआईएस देश के विभिन्न हिस्सों में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण से संबंधित मुद्दों पर विषयगत 'संबंधित कार्यक्रम' आयोजित करने के लिए 'ज्ञान भागीदार' के रूप में वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। 27 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में पूर्वावलोकन समारोह के सफल आयोजन के बाद एसोचैम, भारत के सहयोग से 'शहरी क्षेत्रों के लिए त्वरित जन परिवहन प्रणालियां : अवसर और चुनौतियां' विषय पर एक दिवसीय 'संबंधित कार्यक्रम' 13 मार्च 2018 को कोलकाता में आयोजित किया गया।

उद्घाटन सत्र का शुभारंभ सुश्री परमिंदर जीत कौर, निदेशक (पूर्वी और पूर्वोत्तर), एसोचैम के भाषण के साथ हुआ। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। श्री संजय झुनझुनवाला, अध्यक्ष (पूर्वी क्षेत्र), एसोचैम और डॉ. कुमार विनय प्रताप, संयुक्त सचिव (बुनियादी ढांचा, नीति एवं वित्त), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वागत भाषण दिए। इसके बाद श्री सुन–सिक ली, वरिष्ठ निवेश परिचालन विशेषज्ञ, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, बीजिंग ने एक प्रस्तुति दी। श्री राकेश रंजन, सलाहकार, नीति आयोग, नई दिल्ली, ने मुख्य प्रस्तुति दी। डॉ. मंगू सिंह, प्रबंध निदेशक, दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ने उद्घाटन भाषण दिया। सत्र का समापन आरआईएस के रिसर्च एसोसिएट डॉ. प्रियदर्शी दाश के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

वार्षिक बैठक से पहले आयोजित संबंधित कार्यक्रम में जिन विषयों पर पैनल परिचर्चाएं हुईं वह हैं: शहरी क्षेत्रों के लिए त्वरित जन परिवहन प्रणालियां (एमआरटीएस) : निवेश के अवसर, वित्तीय स्थायित्व एवं नियामकीय रूपरेखा आर्थिक दृष्टि से एमआरटीएस के सतत परिचालन; तथा शहरी क्षेत्रों के लिए एमआरटीएस में निवेश के अवसर और सतत भावी शहरी गतिशीलता के लिए तकनीकी विकल्प।

समापन सत्र में श्री सुभोमय भट्टाचार्जी, सलाहकार, आरआईएस ने सम्मेलन से संबंधित रिपोर्ट पेश की। सुश्री बंदना प्रेयशी, निदेशक (बहुपक्षीय संस्थान), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और श्री राकेश रंजन, सलाहकार, नीति आयोग ने विशेष भाषण दिए। एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप सिंह खरोला ने विशेष समापन भाषण दिया। कार्यक्रम का समापन सुश्री परमिंदर जीत कौर, निदेशक (पूर्वी एवं पूर्वोत्तर), एसोचैम और श्री सुन–सिक ली, वरिष्ठ निवेश परिचालन विशेषज्ञ, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, बीजिंग के धन्यवाद ज्ञापनों के साथ हुआ।

विस्तृत कार्यक्रम आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

'डेवलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू' का विमोचन

भारत सरकार के माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री एम. जे. अकबर 'डेवलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू' लोकारपण करते हुए।

हाल के महीनों में विकासशील देशों के साथ विकास सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहल की गई हैं और गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों ही मामलों में कई मील के पत्थर सफलतापूर्वक पार कर लिए गए हैं। इसने न केवल वैश्विक विकास के लिए भारत के प्रयासों के संदर्भ में, बल्कि त्रिकोणीय और दक्षिण–दक्षिण सहयोग के संदर्भ में भी व्यापक वैश्विक अहमियत हासिल कर ली है, क्योंकि कई अन्य विकासशील देशों ने भी अपने इसी तरह के प्रयासों में काफी तेजी ला दी है। इस समय समस्त विवरण राष्ट्रीय और अन्य स्थलों पर बिखरे या फैले हुए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आरआईएस ने *'डेवलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू (डीसीआर)'* नामक मासिक पत्रिका में इस उभरती गतिशीलता को रेखांकित करने की योजना बनाई है।

'डीसीआर' में द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग प्रयासों की समीक्षा एवं विश्लेषण करने, विकास सहयोग से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रमों एवं मुद्दों पर प्रकाश डालने के साथ–साथ इसके स्पष्ट रुझानों और पैटर्न को रेखांकित करने का इरादा है। बदलते परिदृश्य में विभिन्न तौर–तरीके और अलग–अलग विचार उभर कर सामने आ रहे हैं। 'डीसीआर' का उद्देश्य संबंधित इससे जुड़े सभी संभावित बहुलताओं के साथ 'विकास वादा' की धारणा के जरिए विभिन्न घटनाक्रमों पर प्रकाश डालने के साथ–साथ पाठकों को सूचित करना भी है।

माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री एम. जे. अकबर ने 29 मार्च 2018 को नई दिल्ली में 'डीसीआर' का विमोचन किया।

अपने ओजस्वी भाषण में माननीय मंत्री ने यह बात रेखांकित की कि विकास सहयोग को लोकोपकारी मनन की अंतर्निहित ताकत के साथ साझा समृद्धि के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। कार्यक्रम का आरम्भ एक पैनल परिचर्चा के साथ हुआ और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। श्री शेषाद्रि चारी, सदस्य, संचालन परिषद, आरआईएस ने सत्र की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित पैनलिस्ट थेः श्री प्रशांत अग्रवाल, संयुक्त सचिव (डीपीए–1), विदेश मंत्रालय; डॉ. कौस्तुव बंदोपाध्याय, निदेशक, पीआरआईए; डॉ. हर्ष वी. पंत, प्रतिष्ठित फेलो, ओआरएफ; डॉ. बेनार्ड मुओक, निदेशक, सेंटर फॉर रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (सीआरआईटी), जरामोगी ओगिंगा ओडिंगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केन्या; सुश्री कैरिन कोस्टा वैजक्वेज, शोधकर्ता एवं सलाहकार, अंतरराष्ट्रीय मामलों का स्कूल, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी; श्री सुधांशु एस. सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ह्यूमेनिटेरियन एड इंटरनेशनल; और प्रो. मिलिन्दो चक्रबर्ती, विजिटिंग फेलो, आरआईएस।

'डीसीआर' के विमोचन से पहले प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने कार्यक्रम का संदर्भ पेश किया और डॉ. मोहन कुमार, कार्यवाहक अध्यक्ष, आरआईएस ने सत्र की अध्यक्षता की। माननीय श्री सिद्धार्तो रजा सूर्योदयपुरो, राजदूत, इंडोनेशिया गणराज्य का दूतावास; माननीया सुश्री चित्रांगनी वागीसवारा, उच्चायुक्त, लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य श्रीलंका का उच्चायोग; माननीय श्री बराका एच. लुवांडा, उच्चायुक्त, संयुक्त गणराज्य तंजानिया का उच्चायोग; और प्रोफेसर अनुराधा चेनॉय, अध्यक्ष, एफआईडीसी ने विशेष भाषण दिए।

कार्यक्रम का समापन श्री अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस के समापन भाषण के साथ हुआ। ■

न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ संवाद

आरआईएस ने नई दिल्ली में 8 जनवरी 2018 को न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया। उद्घाटन सत्र में जिन गणमान्य व्यक्तियों की ओर से अपना परिचय प्रस्तुत किया गया उनमे शामिल थेः श्री सायरस कामाऊ, किहुहा, मुख्य वैज्ञानिक, अवसंरचना (इंजीनियरिंग) एवं आईसीटी, राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार आयोग, केन्या गणराज्य; सुश्री हीदर हॉलो, एनवाईयू; श्री अरिया दास, एनवाईयू; सुश्री मारिया फ्लोरेंसिया कोलाडोस, विदेश व्यापार अधिकारी, सांता फे सरकारी निवेश एवं विदेश व्यापार एजेंसी, अर्जेंटीना गणराज्य।

माननीय सांसद डॉ. जयराम रमेश उद्घाटन भाषण देते हुए।

उद्घाटन सत्र के बाद प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। श्री अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस ने इस सत्र की अध्यक्षता की। माननीय सांसद डॉ. जयराम रमेश ने उद्घाटन भाषण दिया। डॉ. एस.आर. राव, सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष भाषण दिया। प्रोफेसर थॉमस पोग, दर्शन शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रचनात्मक (लीटनर) प्रोफेसर, येल विश्वविद्यालय ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वैश्विक समाज पर विशेष व्याख्यान दिया।

इसके बाद 'भारतीय अर्थव्यवस्थाः विकास की प्राथमिकताओं' पर एक संवादात्मक चर्चा हुई जिसमें श्री सुभोमय भट्टाचार्जी, सलाहकार, आरआईएस और डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस ने अपने–अपने विचार प्रस्तुत किए। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर आयोजित संवादात्मक सत्र में डॉ. अशोक जैन, सलाहकार (आरडी), नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र में भारत सरकार के प्रतिनिधि ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। इसके बाद बहुपक्षवाद, लोकतंत्र और आर्थिक विकास पर परिचर्चा का संचालन भी आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने ही किया। इसमे : श्री राजीव खेर, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस; डॉ. एस.वाई. कुरैशी, भारत के पूर्व निर्वाचन आयुक्त; और डॉ. संजय बारू, महासचिव, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की) ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में आईटीडीसी विज्ञान राजनय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का भी उद्घाटन हुआ। ■

अर्जेंटीना की जी20 अध्यक्षता पर चर्चा

ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना ने जी20 की अगली अध्यक्षता संभाली है। इसने प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र और जी20 शिखर सम्मेलन के संभावित परिणाम पहले ही निर्धारित कर दिए हैं। इस संदर्भ में आरआईएस ने जी20 पर एक समर्पित कार्यकलाप कार्यक्रम शुरू किया है और इसके तहत 26 फरवरी 2018 को सेमिनार रूम, एनएमएमएल, नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 'अर्जेंटीना की जी20 अध्यक्षता के अवलोकन' पर एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया।

कार्यक्रम श्री शक्ति सिन्हा, निदेशक, एनएमएमएल और प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत भाषणों के साथ शुरू हुआ। श्री शक्तिकांत दास, जी20 के लिए भारत के शेरपा ने सत्र की अध्यक्षता की। श्री अमर भट्टाचार्य, वरिष्ठ फेलो, वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं विकास, ब्रुकिंग; प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल, आरबीआई चेयर प्रोफेसर, विकास अध्ययन केंद्र; श्री आलोक ए. डिमरी, संयुक्त सचिव (एमईआर), विदेश मंत्रालय, और डॉ. रामकिशन एस. राजन, वाइस–डीन (अनुसंधान) और प्रोफेसर, ली कुआन इयू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर मुख्य पैनलिस्ट थे। इसके बाद हुई परिचर्चा में उपस्थित बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया।

एसडीजी ने गरीबी को सर्वत्र और इसके सभी रूपों में समाप्त करने का लक्ष्य रखा

आरआईएस सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के क्रमिक उद्भव और सितंबर 2015 में इन्हें अपनाने के बाद से ही इनसे सक्रिय तौर पर जुड़ा रहा है। एसडीजी के प्रमुख कार्यकलाप कार्यक्रम के तहत आरआईएस ने विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण से एसडीजी के स्थानीयकरण पर फोकस करते हुए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया में एसडीजी के एजेंडे के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए अथक प्रयास किए हैं। आरआईएस ज्ञान साझेदारियों को मजबूत करने के लिए एसडीजी से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रबुद्ध मंडलों (थिंक–टैंक) के साथ–साथ भारत स्थित संगठनों के साथ भी सहयोग कर रहा है। भारत सरकार का नीति आयोग भारत में एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए समन्वय स्थापित करने के साथ–साथ इस क्षेत्र में अगुवाई करने की दृष्टि से प्रमुख (नोडल) एजेंसी है।

वर्ष 2016 से ही नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र भारत और आरआईएस ने विभिन्न एसडीजी पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त रूप से कई उच्चस्तरीय राष्ट्रीय परामर्शों का आयोजन किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र उच्चस्तरीय राजनीतिक फोरम, जहां

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य भाषण देते हुए।

उसने औपचारिक रूप से अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 2017 प्रस्तुत की, के साथ–साथ 14–19 जुलाई, 2017 के दौरान न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय और संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन न्यूयॉर्क कार्यालय में उच्चस्तरीय पैनल परिचर्चाएं भी आयोजित कीं।

अपने इन प्रयासों के तहत आरआईएस ने नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र भारत के साथ मिलकर 'गरीबी को सर्वत्र इसके सभी रूपों में समाप्त करने' के उद्देश्य से 14 मार्च 2018 को नई दिल्ली में 'लक्ष्य 1' पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार ने इस अवसर पर मुख्य भाषण दिया। डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने विशेष भाषण दिया।

कार्यक्रम का आरम्भ डॉ. अशोक कुमार जैन, सलाहकार, नीति आयोग के स्वागत भाषण के साथ हुआ। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने आरंभिक भाषण दिया। श्री यूरी अफानासीव, भारत में संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक और श्री अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग ने अपने–अपने दृष्टिकोण पेश किए। कार्यक्रम का विस्तृत एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

'आईओआरए की दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता' पर पैनल परिचर्चा

आरआईएस ने 20 जनवरी 2018 को 'आईओआरए की दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता और आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन' पर एक पैनल परिचर्चा का आयोजन किया। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग विभाग के उप महानिदेशक डॉ. अनिल सुकलाल प्रमुख वक्ता थे। डॉ.मोहन कुमार, उपाध्यक्ष, आरआईएस ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। श्री आलोक ए. डिमरी, संयुक्त सचिव (एमईआर), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और श्री बी. जे. जॉबर्ट, दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग, के कार्यवाहक उच्चायुक्त/मंत्री पूर्णाधिकार–युक्त महादूत

परिचर्चा में भाग लेते विशिष्ट प्रतिभागी।

ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत किये। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों नें परिचर्चा में भाग लिया

'आसियान–भारत @ 25: सिंहावलोकन और आगे की राह' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

आसियान–भारत साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) ने 12 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में 'आसियान–भारत @ 25: सिंहावलोकन और आगे की राह' पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। स्वागत भाषण प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस द्वारा और उद्घाटन भाषण राजदूत मोहन कुमार, उपाध्यक्ष, आरआईएस द्वारा दिया गया था। भारत में इंडोनेशिया के राजदूत माननीय श्री सिद्धार्तो रजा सूर्योदयपुरो ने विशेष भाषण दिया। श्री सुधीर देवारे, अध्यक्ष, आरआईएस अनुसंधान सलाहकार परिषद एवं पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने भी अपना समोधन पेश किया। प्रो. प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी ने ई–संग्रह पर एक प्रस्तुति दी।

आसियान–भारत संबंधों पर एआईसी–आरआईएस के ई–संग्रह का विमोचन

इस कार्यक्रम के दौरान आसियान–भारत संबंधों में आरआईएस के योगदान के ई–संग्रह का विमोचन भी किया गया। सम्मेलन को तीन सत्रों में विभाजित किया गया थाः लुक ईस्ट से लेकर एक्ट ईस्ट तकः संवाद साझेदारी से लेकर रणनीतिक साझेदारी तक भारत की यात्रा; आसियान–भारत आर्थिक साझेदारी पर उपलब्धि एवं आगे की राह; और एक एकीकृत एशिया में आसियान एवं भारतः आगे की राह।

कंबोडिया, वियतनाम थाईलैंड और इंडोनेशिया के वरिष्ठ विद्वानों ने परिचर्चा में भाग लिया। दिल्ली स्थित आसियान के मिशन प्रमुखों ने भी इसमें भाग लिया और अपने वरिष्ठ प्रतिनिधियों को नामित किया। सम्मेलन में प्रतिभागी, सरकारी अधिकारी, प्रोफेशनल, शिक्षाविद, शोधकर्ता और मीडिया कर्मी भी प्रतिभागी थे। सम्मेलन के समापन पर डॉ. प्रबीर डे ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

भारत–ब्राजील–दक्षिण अफ्रीका पर विचार मंथन

आरआईएस ने हाल ही में आईबीएसए फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत भारत–ब्राजील–दक्षिण अफ्रीका संवाद पर विचार मंथन सत्र 27 मार्च 2018 को आरआईएस में आयोजित किया गया। श्री अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस ने इस सत्र की अध्यक्षता की। सुश्री कैमिला अमोरिम जार्डिम, आरआईएस में आईबीएसए फेलो रिसर्चर, (पीयूसी–रियो (ब्राजील) में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी अभ्यर्थी एवं ब्रिक्स पॉलिसी सेंटर (ब्राजील) में अनुसंधान सहयोगी) और श्री डेनियल मार्टिन्स सिल्वा, आरआईएस में आईबीएसए फेलो रिसर्चर, (सैन टियागो डेंटास कार्यक्रम (ब्राजील) से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एमएससी और दक्षिण–दक्षिण सहयोग अनुसंधान एवं नीतिगत केंद्र (ब्राजील) में अनुसंधान सहयोगी) ने अपने–अपने मुख्य शोध निष्कर्ष प्रस्तुत किए। प्रस्तुतियों के पश्चात् प्रतिभागियों ने खुली परिचर्चा में अपने विचार प्रस्तुत किये।

आरआईएस–आईबीएसए के फेलो अपने शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए।

डिजिटल इकोनॉमी को समझनाः यह क्या है और यह कैसे एशिया में बदलाव ला सकता है?

आरआईएस स्थित आसियान–इंडिया सेंटर (एआईसी) ने एशियाई विकास बैंक संस्थान (एडीबीआई) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 21–22 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में 'डिजिटल अर्थव्यवस्था को समझनाः यह क्या है और यह कैसे एशिया में बदलाव ला सकता है?' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। एआईसी के समन्वयक डॉ. प्रबीर डे ने स्वागत भाषण दिया। डॉ. चुल जू किम, डिप्टी डीन, एडीबीआई ने आरंभिक भाषण दिया और कार्यशाला संबंधी परिचय कार्य डॉ. अलादीन डी. रिलो, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, एडीबीआई द्वारा संपन्न हुआ। नई दिल्ली स्थित सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय संघ (नैसकॉम) के उपाध्यक्ष श्री प्रशांतो रॉय ने स्वागत भाषण दिया। मुख्य भाषण श्री अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिया गया। एशियाई और अफ्रीकी देशों के लगभग 60 प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

कार्यशाला के शामिल प्रतिभागी।

इन विषयों को समझने के लिए कार्यशाला को आठ सत्रों में आयोजित किया गयाः डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे कि बिग डेटा, मोबाइल प्रौद्योगिकी, एवं इंटरनेट; समावेशी व्यापार को सुविधाजनक बनाने में डिजिटल अर्थव्यवस्था की भूमिका; एशिया में भुगतान करने एवं ऋण देने पर वित्तीय प्रौद्योगिकी का असर; 'डिजिटल अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा दें और किन–किन महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाएं' पर कंट्री पैनल परिचर्चा के लिए विशेष सत्र; डिजिटल दुनिया में प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं शिक्षा की भूमिका; विश्वास, गोपनीयता एवं पारदर्शिता पर डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करना और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने एवं प्रबंधित करने की नीतियां। समापन भाषण डॉ. चुल जू किम और डॉ. प्रबीर डे द्वारा दिए गए। अंत में, आरआईएस स्थित एआईसी में सलाहकार डॉ. दुरइराज कुमारसामी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

'आईओआर क्षेत्र के लिए अनुसंधान प्राथमिकताओं' पर परिचर्चा बैठक

हिंद महासागर रिम संघ (आईओआरए) ने नब्बे के दशक से ही आरआईएस के कार्यकलाप कार्यक्रम में अहम स्थान हासिल कर लिया है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में संस्थान ने ब्लू इकोनॉमी फोरम (बीईएफ) की स्थापना की है। इससे पहले आरआईएस ने 'हिंद महासागर में ब्लू इकोनॉमी की संभावनाओं' पर एक अत्यंत उपयोगी रिपोर्ट पेश की थी। नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) पर विचार मंथन करते हुए नीतिगत संक्षिप्तों को भी प्रकाशित किया गया और इसे बीईएफ के वेबपेज पर भी उपलब्ध कराया गया है।

माननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) की सम्मानित उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

कार्यकलाप कार्यक्रम की निरंतरता के तहत आरआईएस ने 16 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में 'आईओआर क्षेत्र के लिए अनुसंधान प्राथमिकताओं' पर एक परिचर्चा बैठक आयोजित की। आईओआरए के 19 सदस्य देशों ने गहन अनुसंधान संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आरआईएस और आईओआरए के सचिवालय के बीच एमओयू को भी मंजूरी दी गयी। परिचर्चा बैठक के दौरान ही माननीय जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त), विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में आरआईएस और आईओआरए सचिवालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए। कार्यक्रम का आरम्भ आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण के साथ

शेष पृष्ठ 12 पर जारी.....

दक्षिण एशिया में और उससे परे श्रीलंका की भूमिका : उभरती नई रूपरेखा

आरआईएस ने नई दिल्ली में 19 जनवरी 2018 को 'दक्षिण एशिया में और उससे परे श्रीलंका की भूमिकाः उभरती नई रूपरेखा' विषय पर श्रीलंका स्थित लक्ष्मण कदिर्गमर संस्थान की कार्यकारी निदेशक डॉ. दिनुशा पंडितरत्ने का एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण के साथ हुआ। राजदूत अशोक सज्जनहार, पूर्व भारतीय राजनयिक ने सत्र की अध्यक्षता की। माननीया सुश्री चित्रांगनी वागिसवारा, लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य श्रीलंका की उच्चायुक्त, नई दिल्ली ने विशेष भाषण दिया।

श्रीलंका स्थित लक्ष्मण कदिर्गमर संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉ. दिनुशा पंडितरत्ने विशेष व्याख्यान देते हुए।

अपने व्याख्यान में डॉ. दिनुशा पंडितरत्ने ने अपने विचारों को दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में श्रीलंका की वर्तमान एवं भावी भूमिका पर व्यापक रूप से केंद्रित किया। उन्होंने विशेष रूप से इस नए विजन पर प्रकाश डाला कि श्रीलंका वर्तमान में एक नई भौगोलिक पहचान अर्थात अपनी जनता द्वारा हिंद महासागर पहचान के बढ़ते दावे के आधार पर नई शुरुआत कर रहा है। अपनी प्रस्तुति के दौरान उन्होंने इस दावे को सही साबित करने के लिए डेटा और रुझानों का उल्लेख किया। श्रीलंका की भूमिका की नई रूपरेखा को आपस में संबंधित इन चार कारकों में रेखांकित किया गयाः पारंपरिक दक्षिण एशियाई पहचान के बजाय हिंद महासागर के केंद्र के रूप में परिभाषित एक नई भौगोलिक पहचान; राजनीतिक कूटनीति के बजाय आर्थिक कूटनीति पर दृष्टि; अतीत में रणनीतिक गुटनिरपेक्षता के बजाय क्षेत्रीय शक्तियों के साथ सतर्क लेकिन सक्रिय जुड़ाव और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का महज पालन करने के साथ–साथ उन्हें नया स्वरूप प्रदान करने की ओर भी अग्रसर होना।

जातीय संघर्ष के लंबे दौर के बाद श्रीलंका वर्ष 2015 से ही एक बढ़ती अर्थव्यवस्था और गठबंधन सरकार के साथ अब तक के सफल प्रयोग के साथ–साथ एक अपेक्षाकृत बेहतर राजनीतिक स्थिरता का अनुभव करता रहा है। एक नई हिंद महासागर पहचान की धारणा हिंद महासागर में इस देश की रणनीतिक अवस्थिति के साथ–साथ श्रीलंकाई जल के जरिए किए जाने वाले व्यापार और वाणिज्य की कुल मात्रा में निहित है। यह देश एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए मध्य मार्ग में अवस्थित है। इससे श्रीलंका को सिर्फ एक छोटे से द्वीप राष्ट्र की तुलना में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्वयं की परिकल्पना करने में मदद मिलती है। हालांकि, श्रीलंका की इस नई पहचान को दक्षिण एशियाई पहचान के साथ उसकी हताशा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय यह श्रीलंका के लिए विस्तारित गुंजाइश को दर्शाता है, ताकि वह इस क्षेत्र में और वैश्विक स्तर पर अपनी बढ़ती भूमिका से लाभ उठा सके। दक्षिण एशिया के भीतर श्रीलंका ने अनेक सामाजिक और आर्थिक संकेतकों के मामले में अपने दक्षिण एशियाई समकक्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, साक्षरता एवं मोबाइल फोन ग्राहकों के मामले में श्रीलंका को भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में माना गया है। आर्थिक मोर्चे पर शेष दुनिया के साथ श्रीलंका का व्यापार पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया है। इसके अलावा, जातीय संघर्ष के लंबे दौर के बाद श्रीलंका में एफडीआई प्रवाह बढ़ गया है। इसी तरह हाल के वर्षों में इस देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यही नहीं, इस क्षेत्र में भविष्य में और ज्यादा विविधीकरण के साथ–साथ मूल्य वर्द्धन के लिए भी अपार गुंजाइश है।

राजनयिक जुड़ाव के संबंध में श्रीलंका ने रणनीतिक रूप से गुटनिरपेक्षता को अपनाया है। हालांकि, शक्तियों के किसी भी वैश्विक गठबंधन से इस देश के अलग रहने को गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत और गुट निरपेक्ष आंदोलन के बीच के अंतर के नजरिए से समझने की जरूरत है। अपनी आजादी के बाद से ही यह देश आर्थिक कूटनीति के बजाय राजनीतिक कूटनीति को प्राथमिकता देता रहा है। हालांकि, समय के साथ ही विषय–वस्तु और दिशा के संदर्भ में राजनयिक जुड़ाव का स्वरूप बदल गया है। श्रीलंका अब दक्षिण एशिया के देशों के साथ–साथ दुनिया के अन्य क्षेत्रों के देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौतों और सीईपीए की संख्या बढ़ाना चाहता है। भारत के पांच दक्षिणी राज्यों के साथ मिलकर यह देश एक आर्थिक उप–क्षेत्र की संभावना की भी परिकल्पना करता है। विचारक आम तौर पर श्रीलंका की वर्तमान राजनयिक

शेष पृष्ठ 10 पर जारी.....

डॉ. बलदेव राज को भावभीनी श्रद्धांजलि

जाने–माने विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक डॉ. बलदेव राज 6 जनवरी 2018 को आकसमिक देहांत हो गया। यह वास्तव में देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बड़ी क्षति है। डॉ. बलदेव राज आरआईएस की संचालन परिषद के सदस्य थे। डॉ. बलदेव राज को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आरआईएस ने 16 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में एक शोक सभा आयोजित की। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग; डॉ. राम रामास्वामी, अध्यक्ष, भारतीय विज्ञान अकादमी (आईएएससी); और श्री अंबुज डी. सागर, प्रमुख, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, आईआईटी, दिल्ली ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित अन्य प्रतिभागियों ने भी डॉ. बलदेव राज की समृति में अपने विचार रखे।

डॉ. बलदेव राज की समृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा।

दक्षिण एशिया में और उससे परे श्रीलंका की भूमिका.....
पृष्ठ 9 से जारी.....

व्यवस्था को एक नई गुटनिरपेक्षता मानते हैं। सबसे पहले, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत और स्वयं गुटनिरपेक्षता आंदोलन के बीच के अंतर को दर्शाता है। श्रीलंका ने संभवतः गुट निरपेक्ष आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के बजाय गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को ही मुख्य रूप से अपना लिया है। कई मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने, बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए निवेश साझेदारों में विविधता, आईओआरए, बेल्ट एवं रोड पहल, बिम्सटेक और अन्य क्षेत्रीय फोरमों में सक्रिय भागीदारी करने, इत्यादि की बदौलत वैश्विक स्तर पर कई देशों के साथ श्रीलंका के जुड़ाव का दायरा बढ़ गया है।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी या राष्ट्र के रूप में श्रीलंका के अनुमानित अभ्युदय से जुड़ा एक और आयाम यह है कि अब वह अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को नया स्वरूप प्रदान करने में अहम योगदान दे रहा है। परंपरागत रूप से यह देश अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और परंपराओं का एक अनुयायी था। हालांकि, अतीत के विपरीत इस देश को अब विशेष अहमियत के साथ देखा जा रहा है और वह अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने लगा है। कोलंबो में अब कई अंतर–सरकारी संगठनों के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्षेत्रीय कार्यालय भी शामिल है, जो इसी साल खुला है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों की संरक्षणवादी नीतियों के कारण पश्चिमी देशों में उदार आर्थिक व्यवस्था को लेकर कायम अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका नियम–आधारित व्यवस्था और क्षेत्रीय एकीकरण के जरिए एक 'हिंद महासागर हब' के विजन का समर्थन करने को तैयार है। इस देश को आर्थिक कूटनीति और कानून के शासन के बीच सकारात्मक संबंध नजर आ रहा है क्योंकि इससे वैश्विक स्तर पर संबंधित देश की स्वीकृति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। श्रीलंका की वर्तमान सरकार ने भी हिंद महासागर के लिए एक आचार संहिता का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, दुनिया के अन्य हिस्सों में छोटे द्वीप देशों को मिलने वाली सफलता श्रीलंका को 'क्षेत्रीय तौर पर प्रेरित वैश्विक जुड़ाव' को पहले से कहीं अधिक सक्रिय रूप से तलाशने के लिए प्रोत्साहित करती है। व्याख्यान के बाद खुली परिचर्चा हुई।

आरआईएस में प्रतिनिधिमंडलों की अगवानी

- श्री यूताका फुनादा, वैश्विक प्रमुख, ऋण आकलन और जोखिम प्रबंधन समूह, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी), टोक्यो की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने 16 फरवरी 2018 को एक संवादात्मक सत्र के लिए आरआईएस का दौरा किया। यह सत्र जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जापान का एक सरकारी वित्तीय संस्थान) और भारत में बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण में इसकी भागीदारी और 'मुक्त एवं खुला भारत–प्रशांत' की अवधारणा के बारे में चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। जेबीआईसी के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में ये शामिल थेः श्री इत्सुकी योशीदा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी), टोक्यो; श्री इचिरो हायाशिदानी, मुख्य प्रतिनिधि, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)।
- झिंजियांग एम ची उइघुर मेडिसिन रिसर्च सेंटर, चीन के एक प्रतिनिधिमंडल ने 1 मार्च 2018 को आरआईएस में चीन की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उइघुर दवा की स्थिति सहित भारत एवं चीन में पारंपरिक दवाओं पर व्यापक चर्चाएं कीं।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे और विकास नीति

आरआईएस ने 12 फरवरी से 9 मार्च 2018 तक नई दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास नीति (आईईआईडीपी): पर अपना प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आइटेक) कार्यक्रम के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। 21 विकासशील देशों के 28 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया।

आरआईएस संकाय के सदस्यगण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास नीति पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ।

कार्यक्रम में इन विषयों पर संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए: अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे एवं विकास नीति; अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा (यूएन–एफएफडी और जी 20); नए वित्तीय संस्थान – एनडीबी और एआईआईबी; एशियाई शताब्दी एवं भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति; ब्लू इकोनॉमी एवं हिंद महासागर रिम संघ; समूह चर्चा/अनुसंधान लेख की तैयारी; एसडीजी संकेतक एवं निगरानी – चुनौतियां; भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक परिवर्तन; और लोगों की भागीदारी को सुदृढ़ बनाना एवं गवर्नेंस में सुधार – भारत में सिविल सोसायटी की भूमिका। प्रख्यात विशेषज्ञों को विशेष व्याख्यान देने और प्रतिभागियों के साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया। विस्तृत कार्यक्रम आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

विज्ञान राजनय पर आईटेक क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आरआईएस ने नई दिल्ली में 8 से 19 जनवरी 2018 तक विज्ञान राजनय पर एक आईटेक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया।

कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र नई दिल्ली में 8 जनवरी 2018 को न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के छात्रों के संग एक संवादात्मक सत्र के साथ संयोजन के रूप में आयोजित किया गया था, जैसा कि आरआईएस डायरी (पृष्ठ 4) के इस अंक में बताया गया है।

आरआईएस संकाय के सदस्यगण विज्ञान राजनय पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ।

कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी आकलन एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी नीति, विज्ञान राजनय के लिए एक संकल्पनात्मक रूपरेखा, और विज्ञान कूटनीति के सैद्धांतिक एवं संकल्पनात्मक रूपरेखा पर विशेष व्याख्यान आयोजित किए गए। इसके बाद विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि चंद्रयान, अंतरिक्ष सहयोग, फार्मा सेक्टर; और कृषि में भारत के अपने अनुभवों पर एक परिचर्चा आयोजित की गई। विशेष व्याख्यानों की अगली श्रृंखला में प्रस्तुत विषय थे: विज्ञान एवं राजनय और दक्षिण–दक्षिण सहयोग के क्षेत्र में विकासशील देश, भारत की विज्ञान कूटनीति, प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं विज्ञान कूटनीति, नए मुद्दे और विज्ञान कूटनीति, एसडीजी और विकास संबंधी प्राथमिकताएं। प्रख्यात विशेषज्ञों ने अपने–अपने व्याख्यानों और प्रतिभागियों के साथ संवादात्मक सत्रों में इन विषयों के विभिन्न आयामों को कवर किया। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बुनियादी ढांचा भारत...
पृष्ठ 1 से जारी.....

करने वाले कारक; विभिन्न बाधाओं को दूर करने के तरीके एवं साधन और बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु सरकार एवं अन्य संबंधित एजेंसियों को संवेदनशील बनाना।

पूर्वावलोकन समारोह 27 फरवरी 2018 को विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एआईआईबी और आरआईएस द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस समारोह के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत भाषण के साथ हुआ। इसके बाद श्री जिन लिक्यून, अध्यक्ष, एआईआईबी ने मुख्य भाषण दिया। भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने उद्घाटन भाषण दिया। श्री सुभाष चंद्र गर्ग, सचिव (आर्थिक मामले), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने संदर्भ तय करते हुए उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को सूचित किया कि एआईआईबी दुनिया का पहला ऐसा बहुपक्षीय संस्थान है जिसे वास्तव में कर्जदारों द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद सर डैनी अलेक्जेंडर, उपाध्यक्ष एवं कॉरपोरेट सचिव, एआईआईबी ने पहली प्रस्तुति दी। डॉ. एम.एम. कुट्टी, अपर सचिव (आर्थिक मामले), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने और विनोद के. जेकब, संयुक्त सचिव (आर्थिक मामले), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष भाषण दिये। उद्घाटन सत्र का समापन प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

'टिकाऊ बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तपोषण प्रतिमान' पर आयोजित अगले सत्र की अध्यक्षता श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास एवं शहरी मामले, भारत सरकार ने की। इस सत्र में भारत सरकार के माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और शिपिंग मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी ने मुख्य भाषण दिया।

प्रो. अमिताभ कुंडू, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस; डॉ. अमर भट्टाचार्य, पूर्व निदेशक, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक मामलों एवं विकास पर जी24 सचिवालय, वाशिंगटन डी. सी.; डॉ. डी.जे. पांडियन, उपाध्यक्ष एवं मुख्य निवेश अधिकारी, एआईआईबी; डॉ. जुनैद कमल अहमद, इंडिया कंट्री डायरेक्टर, विश्व बैंक; और श्री केनिची योकोयामा, कंट्री डायरेक्टर, भारत निवासी मिशन, एशियाई विकास बैंक पैनलिस्ट थे। खुली परिचर्चा में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया।

> "आज भारत में राजमार्ग एवं शिपिंग क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं और यह क्षेत्र प्रमुख कार्यक्रमों यथा 'भारतमाला' और 'सागरमाला' के तहत व्यापक निवेश के अवसर प्रदान करते हैं।"
>
> – श्री नितिन गडकरी

पूर्वावलोकन समारोह में परिचर्चा के दौरान जो मुख्य मुद्दे उभर कर सामने आए वे बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण की मांग बढ़ने से जुड़े हुए थे। इसके साथ ही सार्वजनिक संसाधनों की भूमिका आगे भी महत्वपूर्ण रहने के बावजूद निजी पूंजी को कुशलतापूर्वक जुटाने की जरूरत होगी। यही नहीं, पारंपरिक बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों के साथ–साथ उन सबका ध्यान समावेशी, सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर केंद्रित हो गया है। उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को सड़कों, मेट्रो रेलवे, बंदरगाहों, डिजिटल बुनियादी ढांचे, स्मार्ट सिटी, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि के रूप में बुनियादी ढांचे में भारी–भरकम निवेश की आवश्यकता होगी, ताकि हाल के वर्षों में इन अर्थव्यवस्थाओं में दर्ज की गई विकास की तेज गति को आगे भी बनाए रखा जा सके। इस अभियान के तहत विशेषकर विभिन्न देशों के एकीकृत विकास के नजरिए से विकास बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस उपरांत सत्र में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण पर भी एक उच्चस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें विशेषज्ञों ने इन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया: त्वरित जन परिवहन प्रणालियां; बंदरगाह एवं तटीय बुनियादी ढांचा; शहरी विकास, डिजिटल बुनियादी ढांचा, समावेशी; सुदृढ़ एवं अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा; क्षेत्रीय विकास, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा; जल एवं स्वच्छता और संसाधन जुटाने में पीपीपी एवं नवाचार।

पूर्वावलोकन समारोह का विस्तृत कार्यक्रम आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

'आईओआर क्षेत्र के लिए अनुसंधान प्राथमिकताओं'...
पृष्ठ 8 से जारी.....

हुआ। आईओआरए के महासचिव श्री के. वी.भगीरथ ने विशेष भाषण दिया। माननीय जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त), विदेश राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष भाषण दिया।

डॉ. एस.के. मोहंती, प्रोफेसर, आरआईएस, के भाषण के बाद एक परिचर्चा आयोजित की गई। डॉ. पंकज झा, वैश्विक सहभागिता के लिए सहायक प्रोफेसर एवं सहायक डीन, ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स; डॉ. रुचिता बेरी, वरिष्ठ शोध सहयोगी एवं समन्वयक, अफ्रीका, एलएसी एवं संयुक्त राष्ट्र, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान; श्री अमरेन्द्र खटुआ, पूर्व महानिदेशक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद; राजदूत आफताब सेठ, चेयरमैन एवं सीईओ, इंडिया ग्लोबल लिंक कंपनी लिमिटेड; मॉरीशस में भारत के पूर्व उच्चायुक्त श्री अनूप मुद्गल; और डॉ. स्वर्ण सिंह, प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, संगठन एवं निरस्त्रीकरण केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने इसमे भाग लिया।

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

प्रो. सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- नई दिल्ली में 9 जनवरी 2018 को विदेश मंत्रालय द्वारा 'संघर्ष से संसद तक की यात्रा' पर आयोजित प्रथम पीआईओ–सांसद सम्मेलन में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 10 जनवरी 2018 को नीति आयोग द्वारा 'आर्थिक नीतिः आगे की राह' पर माननीय प्रधानमंत्री के साथ अर्थशास्त्रियों और क्षेत्र विशेषज्ञों की बातचीत में व्यापार और आर्थिक नीतिगत प्राथमिकताओं पर प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 15 जनवरी 2018 को सीआईआई और इजरायली दूतावास, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भारत–इजरायल बिजनेस अभिनव फोरम में 'बढ़ते सतत व्यापार और निवेश' पर परिचर्चा की अध्यक्षता की।
- नई दिल्ली में 15 जनवरी 2018 को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जैव–बैंकिंग सुविधाओं से संबंधित पूर्व–प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए आयोजित विशेषज्ञ समिति की बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 23–24 जनवरी 2018 को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) और आर्थिक एवं सामाजिक अनुसंधान परिषद (ईएसआरसी), ब्रिटेन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'भारत में शहरी बदलाव' पर सहयोगात्मक अनुसंधान पर संयुक्त बैठक की परिचर्चा में प्रतिभागी।
- नई दिल्ली में 5 फरवरी 2018 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति 2017–18 पर सीआईआई समिति की दूसरी बैठक में एक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- पेरिस में 8 फरवरी 2018 को ओईसीडी विकास केंद्र द्वारा 'विकास रणनीतियों पर पुनर्विचार' पर आयोजित विशेषज्ञ बैठक के दौरान 'विकास प्रतिमानों का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य' पर सत्र में प्रमुख वक्ता थे।
- पेरिस में 9 फरवरी 2018 को दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और ओईसीडी विकास केंद्र द्वारा 'एक नए विकास संदर्भ में दक्षिण–दक्षिण सहयोगः कार्रवाई के लिए आम सहमति वाले एजेंडे की ओर' पर आयोजित बैठक में 'वैश्विक चुनौतियों से पार पाने के लिए एसएससी' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- इंदौर में 12 फरवरी 2018 को 'समृद्ध शहर और समाज के लिए छात्र–संकाय सहयोग' पर डीएवीवी विश्वविद्यालय और समकालीन अध्ययन केंद्र, इंदौर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित विचार मंथन में 'इंदौर के विकास के लिए सामूहिक प्रयासः शिक्षण संस्थानों की भूमिका' पर एक प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 19 फरवरी 2018 को डब्ल्यूटीओ सेंटर, आईआईएफटी और वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'एमसी–11 उपरांत चरण में डब्ल्यूटीओ' पर आयोजित विचार मंथन सत्र में 'नए मुद्दे : इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य' विषय पर सत्र की अध्यक्षता की।
- नई दिल्ली में 23 फरवरी 2018 को स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव (एसआरआई), ग्रुपऑन हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन की बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 28 फरवरी 2018 को विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा 'खाद्य और पोषण सुरक्षाः डब्ल्यूएफपी इंडिया की देश रणनीतिक योजना 2019–2023' पर आयोजित हितधारक परामर्श के दौरान ओपन हाउस चर्चा की अध्यक्षता की।
- नई दिल्ली में 3 मार्च 2018 को केयर निधि द्वारा 'किसी को भी पीछे मत छोड़ो – सतत विकास लक्ष्यों पर जागरूकता कार्यक्रम पर आयोजित संवादात्मक सत्र' की अगुवाई की।
- नई दिल्ली में 5 मार्च 2018 को आईसीएसएसआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय फेलोशिप की आईसीएसएसआर चयन समिति के सदस्य के रूप में भाग लिया।
- पटियाला में 15 मार्च 2018 को अर्थशास्त्र विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला द्वारा 'चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में अभिनव, ज्ञान संचय और विकास' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया।
- नई दिल्ली में 19 मार्च 2018 को गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और जापान सरकार द्वारा 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2018' पर संयुक्त रूप से आयोजित भारत–जापान कार्यशाला में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 20 मार्च 2018 को नीति आयोग द्वारा 'ब्लू इकोनॉमी' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- वाशिंगटन डीसी में 24 मार्च 2018 को एशियाई अध्ययन संघ (एएएस) के वार्षिक सम्मेलन में 'एएजीसी विजन दस्तावेज' पर एक प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 26 मार्च 2018 को भारत–अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 13वें सीआईआई एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव में 'भारत–ब्रिटेनः अफ्रीका में भावी सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करना' विषय पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की।
- नई दिल्ली में 27 मार्च 2018 को भारत–अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 13वें सीआईआई एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव में 'विकास सहयोग पहलों' पर आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में विशेष प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 28 मार्च 2018 को आईडीएसए द्वारा आयोजित 'भारत–अफ्रीकाः चौथे भारत–अफ्रीका रणनीतिक संवाद में सहभागिता को मजबूत करना – भारत और अफ्रीकाः सुरक्षा सहभागिता को सुदृढ़ बनाना' विषय पर प्रस्तुति दी।

प्रो. एस. के. मोहंती

- 5 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा 'व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौते पर भारत–मॉरीशस संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट पर आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया।
- 5 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित परिचर्चा बैठक के दौरान 'व्यापार और निवेश में एलएसी देशों के साथ भारत की सहभागिता' पर एक प्रस्तुति दी।
- 22–24 जनवरी 2018 के दौरान व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौते (सीईसीपीए) पर मॉरीशस और भारत के बीच आयोजित परिचर्चा बैठक के तीसरे दौर में भाग लिया और मॉरीशस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
- 2 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित परिचर्चा बैठक के दौरान 'सेवा क्षेत्र' पर प्रस्तुति दी।
- 5 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित 'भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौते पर भारत और मॉरीशस के बीच डिजिटल वीडियो सम्मेलन' में भाग लिया।
- 19 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित 'एमसी 11 चरण के उपरांत डब्ल्यूटीओ पर विचार मंथन सत्र' में भाग लिया।
- 22 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित परिचर्चा

बैठक के दौरान 'वर्ष 2025 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर देश की यात्रा के साथ भारत की एलएसी नीति को समक्रमिक बनाने' पर एक प्रस्तुति दी।

- 23 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा 'व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौते पर भारत–मॉरीशस संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट' पर आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया।
- 1 मार्च 2018 को चेन्नई में भू–राजनीति एवं व्यापार के जरिए समुद्री संसाधन–सतत विकास पर आयोजित टेरी–केएएस संसाधन संवाद IV के दौरान 'ब्लू इकोनॉमी विकास का एक नया प्रतिमानः सतत समुद्री सहयोग के प्रति दृष्टिकोण' पर एक प्रस्तुति दी।
- 8 मार्च 2018 को नई दिल्ली में अर्थशास्त्र विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया में 'एसआईडीएस में विकास गतिशीलताः सतत नीतिगत विकल्प की ओर' पर व्याख्यान दिया।
- 13 मार्च 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौते (सीईसीपीए) पर आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया।
- 20 मार्च 2018 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, नीति आयोग द्वारा ब्लू इकोनॉमी पर आयोजित संवाद बैठक के दौरान 'ब्लू इकोनॉमीरू भारत के लिए उभरती चुनौतियों' पर प्रस्तुति दी।
- 22 मार्च 2018 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा 'आईओआरएजी के संस्थागत सुधार के लिए प्रस्ताव' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 24 मार्च 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा एलएसी अध्ययन पर आयोजित परिचर्चा बैठक के दौरान 'प्रशांत गठबंधन के साथ भारत की आर्थिक सहभागिता' पर एक प्रस्तुति दी।
- 28 मार्च 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा व्यापार एवं निवेश में लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के साथ भारत की सहभागिता पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।

प्रो. टी.सी. जेम्स

विजिटिंग फेलो

- 5 जनवरी, 2018 को मारयूर, इडुक्की, केरल में केरल सरकार, कृषि विभाग और केरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वस्तुओं के भौगोलिक संकेत के रूप में मारयूर गुड़ के पंजीकरण पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया और एक भौगोलिक संकेत के पंजीकरण से संबंधित तकनीकी एवं कानूनी मुद्दों तथा किसानों के लिए इस तरह के पंजीकरण के आर्थिक लाभों पर एक प्रस्तुति दी।
- 23 जनवरी 2018 को औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा 'भारतीय औषधि उद्योगः औद्योगिक और तकनीकी उन्नयन की चुनौतियां' विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया और फार्मास्युटिकल नीति एवं भावी एजेंडे पर एक प्रस्तुति दी।
- 10 फरवरी, 2018 को नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'नई दवाओं के विकास और आईपीआर से संबंधित मुद्दों' पर एक प्रस्तुति दी।

डॉ. पी. के. आनंद

विजिटिंग फेलो

- डब्ल्यूएफपी, नई दिल्ली द्वारा 13 और 14 जनवरी 2018 को 'एसडीजी 2 रोडमैप रूपरेखा' पर आयोजित विस्तृत बैठकों में भाग लिया और प्रस्तुतियां दीं।
- टेरी, नई दिल्ली द्वारा 15 जनवरी 2018 और 5 फरवरी 2018 को 'सामाजिक प्रभावों के आकलन, पुनर्वास और पुनरुद्धार संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम' पर आयोजित दो आयोजनों के उद्घाटन सत्र के दौरान विशेष भाषण दिए।
- 'गोलमेज सम्मेलनः एसडीजी के संदर्भ में मूल्यांकन के लिए नई सीमाएं' पर आयोजित सत्र में एक पैनलिस्ट के रूप में भाषण दिए, 'मूल्यांकन में क्षमता निर्माण पर संवादात्मक गोलमेज सत्र' की अध्यक्षता की और नई दिल्ली स्थित भारतीय मूल्यांकन समुदाय (ईसीओआई) द्वारा आयोजित 'इवालफेस्ट 2018' के दौरान 8 और 9 फरवरी को समापन सत्र के दौरान अन्य मूल्यांकन भागीदारों के साथ भाषण दिए।
- टेरी, नई दिल्ली द्वारा 16 जनवरी 2018 को 'एसडीजी लागू करने के बारे में असम अनुभव' पर आयोजित सेमिनार में विशेष भाषण दिए।
- डब्ल्यूएफपी, नई दिल्ली द्वारा 28 फरवरी 2018 को आयोजित 'खाद्य और पोषण सुरक्षा पर हितधारक परामर्श : एसडीजी2 पर डब्ल्यूएफपी इंडिया की देश रणनीतिक योजना' पर सुझाव एवं भाषण दिए।

श्री कृष्ण कुमार

विजिटिंग फेलो

- डब्ल्यूएफपी, नई दिल्ली में 13 और 14 जनवरी 2018 को 'एसडीजी2 रोडमैप रूपरेखा पर मसौदा रिपोर्ट' पर विस्तृत बैठकों में भाग लिया और एक प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 8 फरवरी को भारतीय मूल्यांकन समुदाय (ईसीओआई) द्वारा आयोजित 'मूल्यांकन में क्षमता निर्माण पर संवादात्मक गोलमेज सत्र' में भाग लिया और 'गोलमेज सम्मेलनः एसडीजी के संदर्भ में मूल्यांकन के लिए नई सीमाएं' विषय पर आयोजित सत्र में एक पैनलिस्ट के रूप में भाषण दिए।
- टेरी में 16 जनवरी 2018 को 'एसडीजी लागू करने के बारे में असम अनुभव' पर आयोजित सेमिनार में विशेष भाषण दिए।
- डब्ल्यूएफपी, नई दिल्ली द्वारा 28 फरवरी 2018 को आयोजित 'खाद्य और पोषण सुरक्षा पर हितधारक परामर्श : एसडीजी2 पर डब्ल्यूएफपी इंडिया की देश रणनीतिक योजना' में भाग लिया।

डॉ. के. रवि श्रीनिवास

विजिटिंग फेलो

- आईसीडब्ल्यूए, नई दिल्ली में 8 फरवरी 2018 को 'वैश्वीकरण और क्षेत्रीयवाद में उभरते रुझान' पर आयोजित सेमिनार में 'चौथी औद्योगिक क्रांति, वैश्वीकरण और क्षेत्रीयवाद' पर प्रस्तुति दी।

डॉ. सब्यसाची साहा

सहायक प्रोफेसर

- पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला में 1–16 मार्च, 2018 को 'चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में नवाचार, ज्ञान संचय और विकास' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया और चौथी औद्योगिक क्रांति एवं दक्षिण एशिया पर आयोजित पूर्ण सत्र में 'उद्योग 4.0: मिथक और वृहद वास्तविकताओं' पर प्रस्तुति दी।

iLrd@fjikV

of'od xouil] fodkl igy vkj nf{k.k&nf{k.k lg;kx
आरआईएस, नई दिल्ली, 2018

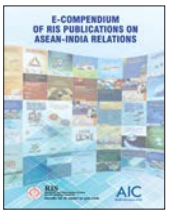

vkfl;ku&Hkkjr lc/kk dk vkjvkbl,l çdk'kuk dk b&lxg] 2018
एआईसी – आरआईएस, नई दिल्ली, 2018

vkfl;ku&Hkkjr vkil e ck/ku oky lc/kk dk l–< cuk jg g] 2018
एआईसी – आरआईएस, नई दिल्ली, 2018

vkjvkbl,l@,,thlh ppk i=

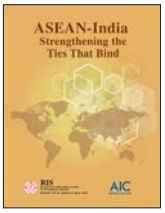

#222 एएजीसी में आपदा और जलवायु जोखिम प्रबंधन में सहयोग द्वारा राजीव इस्सार

#221 एएजीसी में कृषि संबंधी सहयोगः नवाचार और कृषि प्रसंस्करण द्वारा कृष्णा रवि श्रीनिवास

#220 एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर में टिकाऊ कृषि के लिए कृषि दक्षता बढ़ाना द्वारा टी.पी. राजेंद्रन

vkjvkbl,l uhfrxr lf{kIr

#80 चाबहार बंदरगाह और भारत द्वारा सुभोमय भट्टाचार्जी, सलाहकार, आरआईएस

,QvkbVh,e uhfrxr lf{kIr

पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय की पहुंच एवं विस्तार और नवाचारों को प्रोत्साहन , आरआईएस, संख्या 1, नई दिल्ली, 2017

vkjvkbl,l Mk;jh

वॉल्यूम 14 नंबर 1, जनवरी 2018

vkjvkbl,l ladk; }kjk ckgj çdk'kuk e ;kxnku

चतुर्वेदी, सचिन. 2018. 'एएजीसीः समृद्ध भारत–प्रशांत क्षेत्र की ओर अग्रसर'. *टीजीआईआई इंडिया एंड वर्ल्ड* भारत–अफ्रीका के साझा सपनों पर विशेष अंक, वॉल्यूम 1 नंबर 4

चतुर्वेदी, सचिन (सह–संपादन). 2018. दक्षिण एशिया में विनिर्माण और नौकरियांः सतत आर्थिक विकास के लिए रणनीति. नई दिल्लीः स्प्रिंगर.

चतुर्वेदी, सचिन. 2018. 'भारत–प्रशांत में स्थिरता की कुंजी है भारत–आसियान संबंध'. *हिंदुस्तान टाइम्स,* 26 जनवरी.

डे, प्रबीर. (संपादन) 2018. बिम्सटेक के बीस साल : बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना. बिम्सटेक सचिवालय, ढाका.

डे, प्रबीर. 2018. 'भारत कैसे व्यापार संरक्षण का सामना करता है? व्यापार बाधाओं का एक विश्लेषण', कोरियाई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति संस्थान (केआईईपी) (संपादन) में व्यापक क्षेत्रीय रणनीतियों का अध्ययन : एकत्रित प्रपत्र। सियोल.

डे, प्रबीर. 2018. 'क्षेत्रीय सहयोग के लिए नया मॉडल है भारत–आसियान'. *द इकोनॉमिक टाइम्स* 26 जनवरी 2018

डे, प्रबीर. 2018. 'बीबीआईएन चुनौतियां'. ट्रेड इनसाइट. 13, संख्या 3

डे, प्रबीर. 2018. 'आसियान–भारत साझेदारी के 25 साल का समोरणत्सव मनाना : आखिरकार क्या चीज इसे इतना अनोखा बनाती है?'. *इंडिया फाउंडेशन जर्नल,* वॉल्यूम 6, संख्या 1.

डे, प्रबीर. 2018. 'पूर्वोत्तर भारतः आसियान के लिए एक पुल'. *इंडिया एंड वर्ल्ड,* वॉल्यूम 1, संख्या 3.

कुमारसामी, दुरइराज और सिंह, प्रकाश. 2018. 'वित्त तक पहुंच, वित्तीय विकास और सुदृढ़ निर्यात योग्य क्षमता : एशिया–प्रशांत देशों से प्राप्त अनुभव' *एशियन इकोनॉमिक जर्नल,* जॉन विली प्रकाशन, वॉल्यूम 32, संख्या 1, 15–38.

अग्रवाल, प्रदीप और कुमारसामी, दुरइराज. 2018. 'उभरते एशिया में विदेशी पूंजी प्रवाह का प्रभाव', प्रदीप अग्रवाल (संपादन) में, भारत में आर्थिक विकास में नई जान फूंकना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 209–229.

RIS
Research and Information System
for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4–बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003, भारत । दूरभाषः 91–11–24682177–80
फैक्सः 91–11–24682173–74, ई–मेलः dgoffice@ris.org.in
वेबसाइटः http://www.ris.org.in

Follow us on:

www.facebook.com/risindia @RIS_NewDelhi www.youtube.com/RISNewDelhi

प्रबंध संपादकः तीश मल्होत्रा

अपने देशवासियों का जीवन स्तर बेहतर करने के लिए प्रयत्नशील है भारत

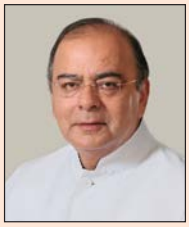

Jh v:.k tVyh
माननीय वित्त मंत्री
भारत सरकार

एआईआईबी के अध्यक्ष श्री जिन लिक्यून, उपाध्यक्ष सर डैनी अलेक्जेंडर, मंच पर विराजमान मेरे अन्य सहयोगी और मित्र, सबसे पहले मैं मुंबई में जून में होने वाली एआईआईबी की इस साल की तीसरी बैठक के लिए एक पूर्वावलोकन समारोह के रूप में इस उद्घाटन सत्र के तहत भारत आए एआईआईबी के अध्यक्ष और उनके सभी सहयोगियों का स्वागत करता हूं। मुझे स्मरण है कि कुछ साल पहले जब हमें भारत को एआईआईबी का एक हिस्सा बनाने के लिए अपने देश में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा था, तो हमने अलग–अलग दृष्टिकोण से इस पर चर्चाएं की थीं। इसके सक्रिय कामकाज के तीन साल बाद मुझे अत्यंत खुशी है कि दूरदर्शिता दिखाते हुए भारत न केवल एक प्रतिभागी, बल्कि एआईआईबी में एक बहुत ही सक्रिय प्रतिभागी बनने पर सहमत हो गया।

अध्यक्ष की अगुवाई में और सभी सदस्यों एवं उनकी टीम के सहयोग से तीन साल से भी कम समय की छोटी–सी अवधि में ही बैंक अत्यंत प्रभावशाली ढंग से काम करने लगा है। पिछले साल जून में जब मैं दूसरी बैठक के लिए जेजू गया था, तो हममें से कई व्यक्ति इस विचार के साथ वहां गए थे कि हमें इस खूबसूरत द्वीप का मनभावन नजारा देखने के लिए कुछ अतिरिक्त समय मिलेगा। लेकिन मैं इस तथ्य से चकित रह गया कि एआईआईबी में जितनी व्यस्त गतिविधियां थीं वह दावोस में हम जो देखते हैं उससे अलग नहीं थीं या जो हम अन्य बहुपक्षीय संस्थानों की वार्षिक बैठकों में देखते हैं उससे भी अलग नहीं थीं। वहां औपचारिक बैठकें हुईं, अनौपचारिक बैठकें हुईं, द्विपक्षीय बैठकें हुईं, क्षेत्रवार बैठकें भी हुईं, सेमिनार हुए और इस तरह से वहां गतिविधियों की कोई कमी नहीं थी। वास्तव में यह बैंक अत्यंत सीमित अवधि में ही काफी प्रगति कर चुका है। कई परियोजनाएं कार्यान्वयन की ओर अग्रसर हैं और भारत इन सक्रिय परियोजनाओं में से कुछ की तैयारी में सबसे आगे रहा है। इनमें से पांच परियोजनाओं को सक्रिय रूप से स्वयं इस बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसके अलावा भी कई अन्य ऐसी परियोजनाएं हैं, जो सक्रियतापूर्वक विचाराधीन हैं।

एशिया वह क्षेत्र है जहां पारंपरिक रूप से बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की कमी थी। यह वह क्षेत्र है जहां पिछले कुछ दशकों में विकास ने तेज गति पकड़नी शुरू की है। एशिया वह क्षेत्र है जो वास्तव में गरीबी उन्मूलन में जुटा रहा है और जिसे तेजी से विकास करने की जरूरत है ताकि इसे खत्म किया जा सके, वह अपने देशवासियों का जीवन स्तर बेहतर करने की स्थिति में आ सके और उन बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की कमी को पूरा कर सके जिनसे वह जूझता रहा है। जहां तक पूरी दुनिया का सवाल है, यह क्षेत्र विकास के मामले में उसकी अगुवाई करता रहा है। चीन ने लगभग तीन दशकों तक यह बात सही साबित कर दिखाई है कि बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की कमी को पूरा करके और तेजी से विकास कर वह प्रभावशाली ढंग से कई लोगों की नियति को बदल सकता है। पिछले कई वर्षों से भारत भी तेज विकास के पथ पर सफलतापूर्वक अग्रसर रहा है और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का निर्माण भी भारत की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रहा है।

आज भारत न केवल पारंपरिक बुनियादी ढांचे, बल्कि ग्रामीण अवसंरचना को भी इस हद तक विकसित करने की आकांक्षा रखता है जिससे कि लोगों का जीवन स्तर प्रभावशाली ढंग से बेहतर हो सके। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें हम बहुत अच्छा कर रहे हैं जैसे कि हमारे राजमार्ग, हमारे हवाई अड्डे, हमारे बंदरगाह और हमारी बिजली उत्पादकता। उधर, रेलवे जैसे क्षेत्र भी हैं जिनसे जुड़ा बुनियादी ढांचा हमारे पास है, लेकिन हमें उसका आधुनिकीकरण करने और उसकी बेहतरी की गति को तेज करने की आवश्यकता है। शहरी आधारभूत अवसंरचना के बारे में मुझे खुशी है कि इस बार पूर्वावलोकन प्रयासों के तहत हम परंपरागत एक या दो बड़े शहरों से आगे जा रहे हैं और हम अब अन्य भारतीय शहरों की ओर उन्मुख हो रहे हैं जिनमें से कई शहरों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं वास्तव में प्रभावशाली ढंग से काफी बेहतर हो गई हैं।

मुझे यह प्रतीत हुआ है कि इनमें से एक सुझाव यह है कि जून में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि देश भर के इन शहरों के प्रतिनिधियों को भी उन कार्यक्रमों में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में आमंत्रित किया जाएगा जिन्हें वार्षिक सम्मेलन के एक हिस्से के रूप में आयोजित किया जाना है। लेकिन ग्रामीण बुनियादी ढांचा भी भारत के लिए अत्यंत अहमियत रखता है और अपने संसाधनों की सीमा के भीतर, चाहे वह सड़कों के माध्यम से जोड़ना हो या ग्रामीण आवास के लिए प्रावधान हो, ग्रामीण स्वच्छता के लिए प्रावधान हो अथवा विद्युतीकरण हो, ये महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं, जिन्हें हम अपने देश में हासिल करने के लिए अथक कोशिश कर रहे हैं।

मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक हमारी प्राथमिकताओं का सवाल है, वह हमारे घरेलू संसाधनों की संभावना के भीतर और स्वयं इस बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों की सहायता से अवसंरचना लगभग केंद्र में है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इस दूरी को हम प्रभावशाली ढंग से पाटने में सक्षम होंगे। चूंकि यह भारत के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, इसलिए मुझे काफी खुशी है कि बीजिंग और जेजू के बाद मुंबई को इस विशेष सम्मेलन के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है। मुझे पक्का भरोसा है कि प्रत्येक वार्षिक बैठक के साथ ही इस बैंक की गतिविधियों, इसके संसाधनों और इसकी परियोजना का विस्तार होगा।

जैसा कि स्पष्ट किया गया था, बैंक की प्राथमिकता सुगठित, स्वच्छ, हरित है। यह भी संभवतः हर साल और हर आयोजन के साथ बड़ी हो जाएगी। मुझे यकीन है कि अध्यक्ष की अगुवाई में और उनकी टीम के सक्रिय सहयोग से यह संभव होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि विशेष रूप से अध्यक्ष प्रतिभाशाली व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा पूल रखने को इच्छुक हैं। जहां तक भारत का सवाल है, बैंक निश्चित रूप से कामयाबी की सीढ़िया चढ़ रहा है। भारत में इस वार्षिक बैठक में आप और आपकी टीम की मौजूदगी को देखते हुए हम भाग्यशाली हैं। मुझे यकीन है कि यह पूर्वावलोकन समारोह, जिसका आरम्भ आज हुआ है, वह आवश्यक उपलब्धि अवश्य हासिल कर लेगा जो आपके अंतर्मन में है। आपको मेरी शुभकामनाएं और मुझे पक्का भरोसा है कि जून में होने वाला यह सम्मेलन, जिसके लिए हम आठ प्रारंभिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, काफी कामयाब साबित होगा। धन्यवाद।

---

27 फरवरी, 2018 को नई दिल्ली में आरआईएस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एआईआईबी के वार्षिक पूर्वावलोकन समारोह में दिए गए उद्घाटन भाषण के मुख्य अंश।